बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का बजट 2023-24	-	₹ 78,800 करोड़
योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का बजट	-	₹ 43,700 करोड़
स्थापना बजट	-	₹ 35,100 करोड़
राजस्व बजट	-	₹ 56,983 करोड़
पूंजी बजट	-	₹ 21,817 करोड़

- 2023-24 में बजट अनुमान ₹78,800 करोड़ है, जो कि 2022-23 के ₹ 75,800 करोड़ के बजट अनुमान से 3000 करोड़ अधिक है और 2022-23 के ₹ 72500 करोड़ के संशोधित अनुमान से 6300 करोड़ अधिक है, जो की क्रमशः 3.96% और 8.69% की वृद्धि है ।

- वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 78,800 करोड़ का बजट मुख्य रूप से स्वयं के संसाधनों से वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रमुख घटको में स्वयं के कर राजस्व से 53,565 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 1050 करोड़ रुपये, लघु बचत ऋण से 10,000 करोड़ रुपये, 622 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियो से, 3802 करोड़ रुपये जीएसटी घटक से और केंद्र प्रायोजित योजनायो से 3167 करोड़ रुपये हैं। भारत सरकार से अनुदान सहायता /सामान्य सहायता के रूप में ₹ 1168 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

दिल्ली का आर्थिक परिदृश्य

- दिल्ली का जीएसडीपी वर्ष 2021-22 में 9,04,642 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 10,43,759 करोड़ रुपये प्रचलित बाजार कीमतों पर 15.38% की वृद्धि होने की संभावना है।

- वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 9.18% रहने की संभावना है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7.0% रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 18.50% और स्थिर कीमतों पर 9.14% बढ़ी है।
- दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,89,529 रुपये से वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 4,44,768 रुपये होने की संभावना है, जो 2022- 23 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 14.18% की वृद्धि है।

स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली

इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं-

(ए) पूरे पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर का उन्नयन और सौंदर्यीकरण।

दिल्ली की सड़कों के उन्नयन और सौंदर्यीकरण की पूरी पहल की योजना 10 साल के क्षितिज और 19,466 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ बनाई जा रही है, जिसमें 2023-24 में 2,034 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

(बी) दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 26 नए फ्लाईओवर/अंडरपास/पुल परियोजनाओं का निर्माण।

सरकार 26 नए फ्लाईओवर/ अंडरपास/ पुल परियोजनाओं के निर्माण पर भी जोर देगी। इनमें से 10 परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, 11 परियोजनाएँ डिज़ाइन अनुमोदन के लिए यू टी टीआई पी ई सी को भेजी गई हैं और 5 परियोजनाएँ निविदा की प्रक्रिया में हैं।

(सी) डीएमआरसी के सहयोग से भजनपुरा से यमुना विहार, आजादपुर से रानी झांसी चौराहों और साकेत से पुल प्रहलादपुर तक 3 अद्वितीय डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण।

इन डबल डेकर फ्लाईओवर के निचले डेक पर वाहन चलेंगे जबकि ऊपरी डेक पर मेट्रो रेल दौड़ेगी.

इन तीन अनूठी परियोजनाओं के साथ, सरकार करदाताओं के 121 करोड़ रुपये की बचत करेगी, वित्त वर्ष 2023-24 में तीन डबल डेकर फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए 320 करोड़ रुपये और सड़कों और पुलों की परियोजनाओं के लिए कुल ₹3,126 करोड़ का बजट है।

(डी) 100 फीडर बसों सहित 1600 नई शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना।

आज, 7,379 बसें, दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक, दिल्ली में 600 से अधिक बस मार्गों पर चलती हैं। 2025 के अंत तक, दिल्ली में 10,480 बसों का बेड़ा होगा, जिसमें से 80% यानी 8,280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी।अगले साल दिल्ली में "मोहल्ला बस" नामक एक समर्पित अंतिम-मील कनेक्टिविट योजना शुरू की जाएगी, जो आने वाले वर्ष में 100 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक "मोहल्ला बसों" से शुरू होगी, अगले 3 साल में शहर की सड़कों पर कुल 2180 "मोहल्ला बसें" चलेंगी।

(इ) दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण।

वर्तमान में दिल्ली में 57 बस डिपो हैं। इस सरकार का लक्ष्य 2025 तक दिल्ली की कुल बसों में से 80% को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का है। इसके लिए दिल्ली के सभी 57 बस डिपो के विद्युतीकरण का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसमें से 3 डिपो पहले से ही विद्युतीकृत हैं और 17 बस डिपो जून 2023 तक विद्युतीकृत हो जाएंगे। दिल्ली में सभी 57 बस डिपो दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत हो जाएंगे।

(एफ) दिल्ली में 3 विश्व स्तरीय अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी), 2 बहु-स्तरीय बस डिपो, 2 आधुनिक बस टर्मिनल और 9 नए बस डिपो का निर्माण।

2023-24 में आनंद विहार और सराय काले खां में 3 विश्व स्तरीय आईएसबीटी का विकास किया जाएगा,जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, जो रोजाना लाखों लोगों को सेवा प्रदान करेंगी, और जो बस नेटवर्क, आरआरटीएस और रेलवे स्टेशन के आस-पास मल्टीमॉडल इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में कार्य करेगा। इन पुनर्विकसित ISBTs को बहुत हद तक "बस पोर्ट्स" कहा जा सकता है।

दिल्ली में जल्द ही हरि नगर और वसंत विहार में दो अद्वितीय बहु-स्तरीय बस डिपो होंगे।परिवहन विभाग ने नेहरू प्लेस और नजफगढ़ में डीएमआरसी के सहयोग से सभी यात्री सुविधाओं से परिपूर्ण दो आधुनिक बस टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। 9 नए बस डिपो का निर्माण जोरों पर है

(जी) स्वच्छ यमुना के लिए छह सूत्रीय कार्य योजना।

दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना पर काम कर रही है जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

पहला: नए एसटीपी/डीएसटीपी का निर्माण और अस्तित्व का उन्नयन।

दूसरा: 100% घरों तक सीवर कनेक्टिविटी -. इस वित्तीय वर्ष में "सीवर कनेक्टिविटी के साथ कॉलोनियों" की कुल संख्या 747 से बढ़कर 1317 (यानी सभी कॉलोनियों के 41% से 73% तक) हो जाएगी।

तीसरा: मौजूदा सीवर नेटवर्क की डीसिल्टिंग।

चौथा: नालियों को ट्रैप और डायवर्ट करना- नालों को जेजे क्लस्टर्स और स्लम से डायवर्ट कर मुख्य सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

पांचवां: औद्योगिक इकाइयों को शिफ्ट करना - प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को कंफर्मिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा।

छठा: यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमुख नालों को रोकना:- इस परियोजना के कार्यान्वयन से दिल्ली में उपचारित सीवेज की मात्रा 2015 में 373 एमजीडी से मार्च 2024 तक लगभग 890 एमजीडी तक तेजी से बढ़ जाएगी – जो की आठ वर्ष में लगभग 250% की वृद्धि है ।

शिक्षा

- डॉ. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (एसओएसई) की शुरुआत 2021 में 20 स्कूलों के साथ हुई थी। यह आने वाले साल में बढ़कर 37 हो जायेंगे । अब इनमें करीब 10 हजार बच्चे पढ़ सकेंगे।
- शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को समर्पित दिल्ली के पहले आवासीय सशस्त्र बल तैयारी स्कूल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजफगढ़ के झाड़ोदा गांव में किया। वर्तमान में इस स्कूल में 160 बच्चे पढ़ रहे हैं जो जल्द ही सशस्त्र बलों में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करेंगे।
- सरकार हर स्कूल में चरणबद्ध तरीके से कम से कम 20 नए कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएगी तथा वर्ष 2023-24 में हम इन उपकरणों को 350 स्कूलों में उपलब्ध कराएंगे।
- आने वाले वर्ष 2023-24 में सरकार हमारे सभी शिक्षकों (नियमित, अतिथि और संविदा सहित), वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और डीडीई को नए टैबलेट प्रदान करेगी।
- प्रौद्योगिकी की मदद से, ध्यान के सचेतन अभ्यास और माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से, हमारे बच्चों ने 12वीं कक्षा में 98% परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके अलावा जेईई मेंस में 493 और नीट में 648 बच्चे क्वालीफाई कर सके।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र में ₹16,575 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

पर्यावरण और वन

- दिल्ली की हवा में पीएम-10 की मौजूदगी साल 2014 में 324 पीपीएम थी, जो 2022 में घटकर 223 पीपीएम रह गई है। इसी तरह दिल्ली की हवा में पीएम-2.5 की मौजूदगी साल 2014 में 149 पीपीएम थी, जो 2022 में 103 पीपीएम तक कम हो गई है ।
- पिछले कुछ वर्षों में "गंभीर" वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में भी भारी कमी आई है - 2016 में 26 दिनों से 2022 में 6 दिनों तक हो गई है । इस अवधि के दौरान, अच्छी से मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जो की 109 की तुलना में 163 हो गई है ।
- दिल्ली में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 11.6 वर्ग मीटर है जो देश के किसी भी अन्य मेगा शहरों से अधिक है। दिल्ली की तुलना में, हैदराबाद में प्रति व्यक्ति वन कवर 10.6, बेंगलुरु 10.4, मुंबई 6.0, चेन्नई 2.6, और कोलकाता 0.1 वर्ग मीटर है।
- सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान 84 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन, 609 स्प्रिंकलर और 639 एंटी-स्मॉग गन भी तैनात किये।
- सरकार ने प्रदूषण के विभिन्न कारणों की वास्तविक समय पर पहचान के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है। इससे वायु प्रदूषण से संबंधित डेटा को मजबूत करने के लिए एक नया बेंचमार्क भी स्थापित हुआ है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सहयोग से स्थापित लैब से सरकार को प्रदूषण के सही समय और कारणों की जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। सरकार वास्तविक समय स्रोत वितरण परियोजना को अगले स्तर पर लेने जाने के लिए 11 मोबाइल वैन पूरी दिल्ली में (प्रत्येक जिले में एक) स्थापित कर रही है।

स्वास्थ्य

- दिल्ली सरकार के पास 515 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 4 महिला मोहल्ला क्लीनिक, 175 एलोपैथिक औषधालय, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 30 पॉलीक्लिनिक और 14,244 बिस्तरों की क्षमता वाले 39 मल्टी स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं जो सालाना 4 करोड़ से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
- मोहल्ला क्लीनिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही है, जहां योग्य एमबीबीएस डॉक्टर लोगों का पूरे सेवा भाव के साथ इलाज करते हैं । इन 515 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों में 250 से अधिक नैदानिक परीक्षण और 165 आवश्यक दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं।
- महिला मोहल्ला क्लिनिक में महिलाओं के लिए कई विशिष्ट सेवाएं हैं जिनमें सर्वाइकल कैंसर की जांच और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण सेवाएं शामिल हैं। 04 ऑपरेशनल क्लिनिक हैं और पहले चार महीनों में 42,000 मरीज महिला मोहल्ला क्लीनिक में आए। अगले वर्ष, मौजूदा 04 क्लीनिकों के अनुभवों के आधार पर, सरकार की पूरे शहर में 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है।
- 09 नए सरकारी अस्पताल निर्माणाधीन हैं, जिनमें से चार अगले वित्तीय वर्ष में चालू हो जाएंगे; इससे बिस्तरों की संख्या 14,000 से बढ़कर लगभग 30,000 हो जाएगी।
- पिछले पांच वर्षों में, 5 लाख से अधिक नागरिकों ने केजरीवाल सरकार की "दिल्ली आरोग्य कोष" योजना का लाभ उठाया है।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,742 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

परिवहन

- दिल्ली सरकार की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना शुरू करने वाला दिल्ली पहला राज्य था और 3.5 साल की अवधि के भीतर, दिल्ली की बसों में महिलाओं द्वारा 100 करोड़ से अधिक यात्राएं मुफ्त में पूरी की गई हैं।
- दिल्ली में 34 महिला चालक हैं जो दिल्ली में 12 मीटर लंबी डीटीसी बसें चलाती हैं। यह भारत में किसी भी परिवहन निगम में चालकों के रूप में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी है।
- दिल्ली का अपना ऑल इन वन पब्लिक मोबिलिटी ऐप "**वन दिल्ली ऐप**" नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इससे यात्री बसों को वास्तविक समय में ट्रैक कर किसी भी बस स्टॉप पर किसी भी समय आने वाली अगली बस का सटीक प्रतीक्षा समय जान सकते हैं और साथ ही रियायती कीमतों पर "संपर्क-रहित" टिकट खरीद सकते हैं ।
- दिल्ली में अब तक 1.04 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं । दिसंबर 2022 के महीने में दिल्ली में बिकने वाले कुल वाहनों में 16.7% इलेक्ट्रिक वाहन थे, जो देश में अब तक का सर्वाधिक है। सरकार ने अब तक 145 करोड़ रुपये से अधिक ईवी सब्सिडी के रूप में वितरित किए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सड़क और पुल सहित परिवहन क्षेत्र में कुल ₹9337 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।

श्रम

- कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए पुरे देश में न्यूनतम मजदूरी सबसे ज्यादा दिल्ली में है। श्रम विभाग ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन ₹ 16,792/- प्रति माह, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए ₹ 18,499/- और कुशल श्रमिकों के लिए ₹ 20,357/- प्रति माह निर्धारित किया है, जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

राजस्व विभाग

- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार अयोध्या, द्वारकाधीश, पुरी, वाराणसी, माँ वैष्णो देवी धाम, अजमेर शरीफ, रामेश्वरम, शिरडी, तिरुपति बालाजी, अमृतसर सहित धार्मिक आस्थाओं के 15 स्थानों पर दिल्ली के लगभग 70,000 बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का आयोजन किया है ।
- दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगभग 1100 स्थानों पर छठ घाट और 175 स्थानों पर कांवड़ शिविर लगवाए हैं । इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराने और इसे संरक्षित करने के लिए, सरकार पूरे दिल्ली में लगभग 100 स्थानों पर 'उत्तरायणी महोत्सव' आयोजित करती है।

जल

- दिल्ली जल बोर्ड "स्वच्छ यमुना" परियोजना और "स्वच्छ पानी की 24x7 आपूर्ति" पर मिशन मोड में काम कर रहा है।
- दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की पाइपलाइनों का एक बड़ा नेटवर्क बिछाया है जिससे कि दिल्ली की 1671 अनधिकृत कॉलोनियों में से लगभग 93% में जलापूर्ति संभव हुई है । पिछले 8 साल में दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में करीब 5,138 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है ।

- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति बढ़ाने हेतु मार्च 2025 तक जल की उपलब्धता वर्तमान 995 एमजीडी से बढ़ाकर लगभग 1240 एमजीडी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
- समाज के सबसे गरीब वर्ग को भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, दिल्ली सरकार इस वित्तीय वर्ष में ''जेजे क्लस्टर'' अनधिकृत कॉलोनियों और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 आरओ प्लांट स्थापित करने जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जल क्षेत्र में कुल ₹6,342 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- लगभग 8.82 लाख वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विकलांगों और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ₹ 2,000 से ₹ 2,500 प्रति माह की पेंशन की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 में ₹ 2,962 करोड़ की राशि प्रस्तावित की जा रही है।
- समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कुल ₹ 4,744 करोड़ की राशि रखी जा रही है ।

ऊर्जा

- दिल्ली में पिछले 8 सालों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं।
- दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्रत्येक घर को न्यूनतम बिजली प्रदान करना एक मौलिक अधिकार माना है और वर्ष 2022-23 में दिल्ली के 58.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 84% ने दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाया था।
- दिसंबर 2022 में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली की मसौदा सौर नीति को अधिसूचित किया, जो दिल्ली को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए एक अग्रणी उदाहरण के रूप में स्थापित करेगी। दिल्ली सौर नीति 2022 का लक्ष्य 2025 तक दिल्ली की वार्षिक बिजली की मांग का 25% सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है, जो वर्तमान में 9% है। इसे प्राप्त करने के लिए, नीति में 2025 तक 6,000 मेगावाट की क्षमता के साथ सौर अवसंरचना स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 750 मेगावाट का 'रूफ टॉप सोलर' (आरटीएस) शामिल होगा। नीति का लक्ष्य दिल्ली में लगभग 12,000 हरित रोजगार सृजित करना भी है।
- दिल्ली सरकार आज सबसे कम चार्जिंग टैरिफ वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आगे आई है। EV चार्जिंग के लिए न्यूनतम लागत केवल ₹3 प्रति kWh है। 18 अक्टूबर 2022 को 100 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से पहले 11 का उद्घाटन किया गया है। अन्य 30 चार्जिंग स्टेशनों को मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा और बाकी अगले वित्तीय वर्ष में।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत क्षेत्र में कुल ₹3348 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।